AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed, Open Acces & Google Scholar Indexed International E- Journal
Vol (1&2), Issue (3), Nov -Jan 2024-25 *E-ISSN: 3048-7951*

बिहार में राष्ट्रवाद, 1917–1922 प्रतिरोधो की रूप रेखा

डॉ0 पप्पु ठाकुर
पूर्व शोध छात्र इतिहास विभाग
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

1917–1922 के गाँधी युग का ध्यान आते की मेरी आँखो के सामने एक तस्वीर तैरने लगती है। अपना होश संभालने के बाद मैंने बहुत से आंदोलन देखे है, लेकिन मैं पुरे निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि किसी और आंदोलन ने भातरीय समाज में इतनी उथल, पुथल पैदाना नही की जितनी कि चम्पारण आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन ने की गरीबो की झोपड़ियो से लेकर ऊँचे महलो तक सब कुछ जैसे डोल रहा था गुजायमान हो रका था।
बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन एक नया मोड़ था। असहयोग आंदोलन के दौरान और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित वर्गो तक ही सिमित नही रहा और उसने जन आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया। बिहार में राष्ट्रवाद पर वर्तमान लेखन निसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें आंदोलन का बड़ा सामान्य सा विवरण दिया गया है और उसकी जटिलता पर कोई ध्यान नही दिया गया है। इन विवरणों में राष्ट्रवाद को गया सुविख्यात ऐतिहासिक घटनाओं के इर्द–गिर्द घुमती है। इसके अलावा इस लेखन का पुरा फोकस काँग्रेस और उसके नेताओं की भूमिका पर है सब घटनाओं को भूमिका को हाशिए पर डाल दिया गया है। बिहार में राष्ट्रबाद के बाद के चारण पर कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ है। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण पर कोई सघन अध्यान नही हुआ है। इसलिए यह अध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रवाद के बारे में इतिहास लेखन पर फिरस से विचार की दृष्टि से भी यह अध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह चरण था जब राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित वर्गो के दायरे से बाहर निकलकर जन आंदोलन बन गया था।

राष्ट्रवाद का अधीनस्थ पुलिस के साथ जुड़ाव :–

इस खण्ड में अधीनस्थ पुलिस बल, सिपाहियों जो पुलिस का अधिकांश हिस्साा होते थे। के पहले जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ाव के जाँच को गई है पुलिस ब्रिटिश प्राधिकार का सबसे महत्पूर्ण निशान था और कुल मिलाकर औपनिवेशिक शासन का प्रती थी। वास्तव में आाधुनिक पुलिस को औपनिवेशिक शासन की बढ़ती हुई जरूरतो के अनुसार ही रूप दिया गया था और वह उसी ही जरूरतो को प्रतिबिबित करती थी। नौकरशाही और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच संबंध के बारे में अध्ययनों

का अभाव है। इसके अलावा इस बात का अहसास कराया जाता है कि 1940 के दशक तक नौकरशाही पर ब्रिटिश वर्चस्व रहा। असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि वह किस हद तक पुलिस के खिलाफ लोक शत्रुता, आक्रमण और अवज्ञा की अभिव्यक्ति का वाहक बना आंदोलन के साथ निकट से जुड़ी एक अन्य प्रवृति थी राष्ट्रवादियों द्वारा पुलिस के साथ दोस्ती किए जाने का प्रयास आंदोलन पुलिस बल के निचले तबके में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करने में कामयाब रहा बहुत स्थानो पर असहयोग आंदोलन के दौरान अधीनस्थ पुलिस मैंन बेहतर सेवा शर्तो की माँग करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्रवृत्तियों को कैसे लिया जाए और पुलिस पहचान पर इससे क्या प्रकाश पड़ता है।

सिपाहियों में बहुत असंतोष था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान संगठित विरोध का रूप ले लिया जब वे कई स्थानो पर हड़ताल पर चले गए। लेकिन वे पहले सामान्य हालात में भी विभिन्न तरीको से अपने रोजगार को प्रकृति और शर्ते पर विरोध व्यक्त करते रहते थे जिसे रोजमरा का प्रतिरोध कहा जा सकता है। सिपाही नौकरी से इस्तीफा देकर बार–बार बिमारी की छुट्टी लेकर और अपने काम को ऊटपटांग तरीके से करे अपने असंतोष की व्यक्त करते थे। लेकिन इस तरह का प्रतिरोध सामान्य तौर पर अंसगठित और छिटू–पुट होता था। उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तो की माँग के लिए सिपाहियों हदिारा सेवा शर्तो की माँग के लिए सिपाहियों हदिरा कोई समन्वित प्रयास नही किया जाता था। 1921 में पहली बार संगठित पुलिस विरोध हुआ। बहुत सी बात एक साथ होने से विरोध में तेजी आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत कमी हो जाने और किमते बढ़ जाने के कारण उनकी हालत और भी खराब हो गई। युद्ध के दौरान उन्हे लम्बे समय तक काम करना पड़ता था। फालतू काम करना पड़ता था और छुटियाँ नही मिलती थी। इसके आलावा युद्ध के तत्काल बाद के वर्षो में राजनीतिक और आर्थिक दशाओ ने सिपाहियों का अपने नियोक्ताओं पर दबदबा बढ़ा दिया था। यह वह समय था जब मजदुर संघ गठित किए जा रहे थे और मजदुरो में असंतोष बढ़ रहा था। 1921 में पुलिस संघ गठन हुआ जिसके उद्दद्देश्य थे सभी वैध माध्यमों से उसके सदस्यों के वेतन हैसियत, सेवा शर्तो और मनाबल में सुधार लाना, सभी सदस्यों में संघ भाव पैदा करना सदस्यों के सामान्य हितो को प्रभावित करने वाले मुददों पर विचार करना और उनके हितों की रक्षा करना। पुलिस विरोध में राष्ट्रवाद की अपनी भूमिका तो थी ही। असहयोग के दौरान अंततः सेना और पुलिस से भारतीयों के इस्तीफे का आहवान किया गया। बिहार में बहुत से आदिवासियों ने पुलिस मानहतो की समस्यओं के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई। राष्ट्रवादी आंदोलन ने सिपाहियों का हौसाला बढ़ाया, क्योकि उनके विरोध को अब आसानी से

अलगाया और दबाया नही जा सकता था। सरकार डरी हुई है, कमजोर है और वह कुछ नही कर सकती है इस धारणा ने उन्हे और प्रोत्साहित किया।

असहयोगी सिपाहियों के संपर्क में थे उनकी बैठको में हिस्सा लेते थे और सिपाही की समस्या में दिलचस्पी लेते थे बिहार के विभिन्न हिस्सो में सभाओं को संबोधित करते हुए कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण पुलिस और सेना को सरकार से बाहर निकालना होगा। उन्होने आशा व्यक्त की कि अंततः पुलिस मैंन नौकरी से इस्तीफा देंगे और आंदोलन में शामिल होगे। स्थानीय नेताओं ने पर्चे बाटकर पुलिस से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। अपील में कहा गया कि सेवा से इस्तीफा देकर पुलिस स्वंय को औपनिवेशिक दासता से मुक्त करेगी। पुलिस से भाईयों के तौर पर अपील की गई और साथ ही मातृभूमि और देशवासियों के साथ गददारी करने के लिए उनको फटका भी लगाई गई। अपने ही लोगो के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और नृशंष्ता के लिए उनकी भर्त्सना की गई। राष्ट्रवादियों ने यह कहकर उनको फटकार लगाई कि साइयो को भी 75 और खान सामों को 10रू0 मिलते है और उन्होने केवल 5 था 10 रू0 वालो रोजी–रोटी के लिए अपने ही लोगो का लगातार उत्पीड़न किया। राष्ट्रवादियों ने पुलिसवालों से अनुरोध किया कि वे अपने घर चले जाए और खेती करके अपने बच्चो का भरण–पोषण करे।

पुलिस से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रवादियों का अपील ने सरकार को भयभीत कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन ने पुलिस बल को किस हद तक प्रभावित किया है इसका अनुमान लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक ने विभिन्न जिलनों के पुलिस अधीक्षकों को अनुदेश दिए कि वे असहयोग आंदोलन के प्रति पुलिस के रूख के बारे में रिपोर्ट भेंजे। सभी पुलिस अधीक्षकों का विचार था कि उच्च पद वाले पुलिस अधीकारी सरकार के प्रति निष्ठावान है और आंदोलन के विराधी है। लेकिन वे उप–निरीक्षक और हेड कोंस्टेबल जैसे निचली श्रेणी वाले पुलिस मैंनों की निस्ठा के बारे में निश्चित नही थे। सभी पुलिस अधीक्षकों ने यह भी बताया कि पुलिस बल में सबसे निचले स्तर पर कर्मी बिलकुल भी भरोसे योग्य नही है, कॉस्टेबल उतेने भरोसे योग्य नही है जितने कि वे युद्ध से पहले के काल मे थे। उन्होने यह भी कहा कि कौन्स्टेबल गाँधी का आदर करते है अझैर उन्हे दिव्य शक्ति मानते है। इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने पुलिस बल के निचले वर्ग में अपने लिए सहानुभूति पैदा कर ली थी।

राष्ट्रवादियों की पुलिस बल से अपील, उसके निचले वर्गो में सहानुभूति, राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होने के लिए कुछ सिपाहियों द्वारा इस्तीफा दिया जाना यह सब उनकी अन्य वालो पहचान पर फिर से विचार करने के लिए विवश कर देता है। पुलिस का केवल शासन शक्ति के एजेंटो के रूप में पहचान उनकी वैकल्पिक संभवतः प्रतिच्छेदी पहचानो और संबधो को विचाार के बाहर कर देती है। पुलिस को औपनिवेशिक शासन के मित्र या शत्र के द्वित्वो के रूप में नही देखा जाना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक मुकामों पर शासन के अधीनस्थ कर्मचारी शासन के साथ अपनी निष्ठा का त्याग कर देते है और लोगो और उनके आंदोलन के साथ जुड़ जाते है।

असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस के साथ दोस्ती की धारा के साथ–साथ उसके साथ कटु दुश्मनी की उतनी ही प्रबल धारा भी बह रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर पुलिस के प्रति गहरे गुस्से और शत्रुता के मजबुत प्रवल चल रहे थे। पुलिस के प्रति शत्रुता काफी लंबे समय से घुमड़ रही थी, लेकिन असहयोग आंदोलन दौरान पुलिस की तीब्र और लगातार आलोचना की जाने लगी। जैसी कि उपर चर्चा की गई है असहयोग आंदोलन ने औपनिवेशिक प्राधिकारी के प्रति अवज्ञा और बेहद तिरस्कार की मानसिकता पैदा कर दी थी। स्थानीय पुलिस शासन प्राधिकारी का सबसे स्पष्ट चेहरा थी और शासन और लोगो के बीच वृकराव के बहुत नाजुक बिटु पर खड़ी होती थी। वे शासन के ऐसे बहुत कम एजेंटो मैं से थे जिनके साथ लोगो का सीधा सम्पर्क था। पुलिस कार्यवाही के जरिए औपनिवेशिक शासन का मनमाना और बेहद क्रूर स्वरूप और भारतीय अवाम के प्रति उसकी गैर जवाबदेही वाला रवैया सामने आता था। रक्षाहीन सत्याग्रही का लाठीधारी पुलिसवाले द्वारा बेरहमी से पीटा जाना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का भावात्मक निशान बन गया था। इसके अलावा शासन के उत्पीड़क एजेंट के रूप में पुलिस से सामान्य जनता उसकी बेरोकहोक घटिया क्रूरता और भ्रष्टाचार के कारण बहुत घृणा करती थी। उसका मनमानापन और जुल्म विवाद को मामूली लड़ाई से बढ़ाकर हिंसक मुठभेड़ बना देता था। पुलिस के प्रति गहरी शत्रुता और उस पर बार–बार हमने ने उसके मनोबल को तोड़ दिया था और सरकार के सम्मान को बहुत चोट पहुँचाई। प्राधिकार पर यह चोट सरकार के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द बन गई थी। सरकार ने इस बात पर बल दिया कि सफल प्रशासन जितना प्राधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता के सामान्य माहौल और समाज की वर्तमाल व्यवस्था को बनाए रखने पर निर्भर करता है उतना की कानून के निश्चित प्रवर्तन और प्रशासन तंत्र के काम करने परा पहले सरकार के सम्मान और प्रतिस्ठा के कारण छोटा सा पुलिस बल भी उसके प्राधिकार की रक्षा कर पाता थ। लेकिन

अब औपनिवेशिक प्राधिकारीच को चोह पहुँचने से अब उसे ताकत दिखानी पड़ती थी। पहले उसकी प्रतिस्ठा ही विरोध की संभाना को समाप्त का देती थी।

आधिपत्य लड़ाई के स्थल के रूप में राष्ट्रवाद :–

इस अध्याय का अन्य आयाम यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रवाद अधिपत्य विरोधी संघर्ष का स्थल भी था, क्योकि ब्रिटिश शासन केवल ताकत और उत्पीड़न पर ही आधारित नही था, बल्कि अपने आधियत्यवादी स्वरूप को सामने रखने की कोशिश भी करता था। अध्यनो में स्पष्ट किया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीवे अर्ध आधियत्यवादी थी। यह शासन पैक्स ब्रिहेनिका की विचारधारा, कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश अधिकारियों को लोगो का भाई–बाप बनए जाने और औपनिवेशिक विचारधाराओं को खुराक देने वाली शैक्षिक, कानूनी व्यक्ति सवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सहरा लेता था। ब्रिटिश शासकों ने सहयोगी संरचना था सवैधानिक सुधार पर बल दिया और उसके प्रोन्नत किया। विधार्थी परिषदो और न्यायालयों को सहयोग के पहलुओं के रूप में प्रस्तुत किया गया। असहयोग आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन के विदेशी और अप्रितिनिधिक स्वरूप को सामने रखा जिससे भारत के बहुत संख्यक जन समूह द्वारा अपने शासको को बच्चे की तरह माई–बाप माने जाने का मिथक सुटा। अपने अधिपत्य को स्थापित करने के लिए अंग्रेजो के पास जो भी संस्थागत और विचारधारात्मक स्त्रोतो थे वे विद्रोह के प्रभाव से चरमराने लगे।

बहिष्टाकारो ने ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक हितो और नीतियों को उजागर किया। विभिन्न बहिष्कारो के जरिए राष्ट्रवादी ब्रिटिश सत्ता का तलोच्देन करने और उसके अधिपत्य को चोट पहुँचाने में सफल रहे। अपने अधिपत्य में क्षय को औपनिवेशिक सत्त ने अपनी शक्ति के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में लिया।

असहयोग आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश शान के अप्रतिनिधिक स्वरूप का सामने रखा बल्कि “बल्कि” शासन के प्रतिकूल प्रभावों को भी उजागर किया राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति के पुनरूत्यान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासक को दैत्य, पिशाच, अधार्मिक, कपटी, लूटेरा, बेईमान और भारतीय लोगो के चरित्र पतन के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होने यह भी कहा की शिक्षा और न्यायालक जैसे ब्रिटिश संस्थाओं ने लोगो की आत्मा को कुचला, नेक विचारो को दबाया, लोगो में बुरे संवेगो को उकसाया समाज में विभाजन पैदा किया और परिवार में विवाद बढ़ाए। न्यायालयों को झूठा, धोखधड़ी कपट, बेईमानी, मानव कमजोरी दुष्टता और नीचता के अडडे बताया गया। इस बात को भी

रेखांकित किया गया कि भारत जिसकी एक समय भव्य सभ्यता थी अब ब्रिटिश प्रभाव के कारण आध्यामिकता, वैथरिकता, पुरूत्व शक्ति विहीन हो गया है। हिन्दु और मुस्लिम धर्म को खतरे में बताया गया। रामायण और महाभारत से रूपक ग्रहण करके औपनिवेशिक सत्ता को अकसर रावण बताया जाता था। गाय के रूपक का अकसर रावण बताया जाता था। गाय के रूपक का अकस प्रयोग गाय की रक्षा के लिए संघर्ष बताया जाता था। राष्ट्रवादी अभियान में शुद्धता और अपवित्रता के विचार का आहवान किया जाता था। ब्राहमणों क्षतियाँ और पंडितों के अपने बच्चे स्थान से नीचे गिर जाने की बात की जाती थी। राष्ट्रवाद राष्ट्र के धर्म, संस्कृति, पंरपरा, सम्मान, आध्यात्मिका और बैतिकता का रक्षा के लिए आहवाब बन गया। बहिष्कार के मर्म में औपनिवेशिक सत्ता के सामने नैतिक स्वतंत्रता और आत्मा सम्मान मुदद्ा था। राष्ट्रवादियों ने कहा कि अन्यायी और दमनकारी शासन के साथ सहयोग न करके भारतीय अपने कुद आत्म सम्मान और नैतिक शुद्धता को वापस पा सकते है जो उन्होने पिछले 200 वर्षो में गँवा दी है। राष्ट्रवादी शिक्षा भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा और नैतिकता के लिए रामबाग का काम करेगी। शराब का बहिष्कार भारत को एक बार फिर आचार की दृष्टि से शुद्ध बना देगा। शराब पीना भारतीय परंपरा के विरूद्ध और समाज की नीचे व्यवस्थाओं की विशेषता माना जाता था। पंचायतो लोगो के धर्म, इज्जत और धन का रक्षा करेगी और समाज और परिवार में विभाजक नही बल्कि सद् भावना पैदा करने वाली भूमिका अदा करेगी। खतरे में पड़े ग्रामीण शिल्प अर्थात हथकरघा का शक्तिशाली प्रतीक बन गई। राष्ट्रीय आंदोलन अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई बन गया। राष्ट्रवाद ने विशेष रूप ऐ धार्मिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को लोक संस्कृति में डाल दिया। धर्म निरपेक्ष और पवित्र अब अलग क्षेत्र नही रह गए, बल्कि एक–दुसरे के साथ क्रिया करने लगे।

राष्ट्रवाद को अधिपत्य संघर्ष बना देने से राष्ट्रवाद अवधारणा का विस्तार हो जाता है अग्रेजो को बाहर निकालने सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष–तक सीमित न रह कर औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ संस्कृतिक मुठभेड़ बन जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति के में और उसके आध्यात्मिक सार तत्व की रक्षा, उसे बनाए रखना और सुद्ध करना प्राथमिक जरूरते बन गए। उपनिवेशकों द्वारा इसमें अनाधिकार प्रवेश को किसी भी सुरत में बर्दाश्त नही किया जाना था। पंचायतो के माध्यम से शिक्षा पहनवो और न्यायपालिका के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचाने के निर्माण और फुनरूब्यान का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय का दायरा वही नही था जो पश्चिम का है। यह तात्विक परंपरा को विशेष महत्व दिए जाने पर आधारित था, आत्म शुद्धि, शाकाहार, भोजन शुद्धदता के लिए सरोकार, शराब निषेध इन सभी को भारतीय

Vol (1&2), Issue (3), Nov -Jan 2024-25 E-ISSN: 3048-7951

(परंपरा) और धर्म वैधता प्राप्त होती है। राष्ट्रवादी आधिपत्य परियोजना लोक परंपरा को हटाकर सांस्कृतिक आदर्शीकरण की परियोजना थी मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी परंपरा से तत्व ग्रहण करने वाले इस विमर्श के जाति, लिंग और अल्प संख्यक निहितार्थ थे। इस प्रकार राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक शासन के बीच संघर्ष ऐतिहासिक रूप में समाज के भीतर अधिमत्य के लिए संघर्ष का था।

इस प्रकार इस अध्याय में बिहार में असहयोग आंदोलन की जटिलता का स्पल किया गया है। आंदोलन को लोक विरोधो से ताकत मिली लोगो को आशाओं अऔर आकांक्षाओं के स्वराज के साथ जुड़ जाने के बाद असहयोग आंदोलन ने अपनी लय और गतिविज्ञान को प्राप्त कर लिया और उसकी कार्य सूची अक्सर कांग्रेस नेताओं की कार्यसूची से भिन्न होने लगी। कांग्रेस और औपनिवेशिक सत्ता को इससे सबसे अधिक डर लगता था। आंदोलन कांग्रेस द्वारा निर्धारित अहिंसा के दायरे तक को सिमित नही रहा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुरे असहयोग आंदोलन में कांग्रेस नही बल्कि गाँधी का नाम बार–बार लिया जाता था। लोक कार्यवाहियों को गाँधी के माने जाने आदेशों से वैधता मिलती भी जो उनकी आशाओं और इच्छाओं का प्रतीक बन गए थे। लोग गाँधी को प्राधिकार को वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में देखते थे। न केवल सबलहर्न संघर्षो को आगे लाकर बल्कि प्रतिरोध के अन्य प्रकारो को रेखांकित करे यह अध्यायन राष्ट्रवाद के बहुपरतीय फलको और आयामों को उजागर करता है। यह राष्ट्रवाद को अधिपत्य के स्थल के रूप में भी प्रस्तुत करता हैः–

संदर्भ :–

1. के.के. दत्ता हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीइम मूवमेंट इन बिहार, उखण्ड पटना, बिहार सरकार प्रेस, 1957 पी.एन. ओझा, संपादित हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885–1985 पटना। के.पी. जासवाल रिसर्च इंस्ट्रीटयूट 1985
2. स्टीफन वृनिध्धम, पीजेंट मूलमेद्वान इन कोलोनियल इंडिया नॉर्थ बिहार, 1917–42 केबररा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवसिटी, 1884
3. विनीता दामोदरन, ब्रोकन प्रोमिसिज पॉपुलर प्रोटेस्ट, इंडियन नेशनलिज्म एंड दि कांग्रेस पार्टी इन बिहार 1935–1996 नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस 1942 पपिया घोष दि सिविल डिसओबिडिएण्ड मूवमेन्ट इन बिहार नई दिल्ली मानक, 2008
4. रणजीत गुहा, एलिमेटरी आसपेक्ट्स, ऑस पीजेंट इनसरजेंसी इन कोलोनियल इंडिया, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेंस, 1983 रणजीत गुन्हा, ऑन सम आसपेक्ट्रस ऑफ दि हिस्होरियोग्राफी ऑफ कोलोनियल इंडिया, सबलटर्न स्टडीज।

Vol (1&2), Issue (3), Nov -Jan 2024-25 E-ISSN: 3048-7951

5. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक स्पेशल फाइल सं. 184/1921, 93/1921.
6. बिहार और उड़िसा राजनीतिक स्पेशल फाइल सं. 50/1921 और 75/1921 फीडम मूवमेट पेपर्स एससीआराओ 51, बीएसए,
7. मुरली अटलरी, सबलटर्न स्टडीज प्ट सोशल साइंटिस्ट खंड 16, सं. 3 मार्च 1988.
8. लतासिंह, नेशनल मूवमेन्ट इन बिहार।
9. गुहा एलिएमेंटरी आसपेक्ट्स ऑफ पीजेंट इनसरजेंसी इन कोलोनियल इंडिया।
10. बिहार और उड़ीसा पुलिस प्रशासन रिपोर्ट 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1917, 1918।
11. झा, राज टु स्वराज पश 404 बिहार और उड़ीसा राजनीतिक स्पेशल फाइल सं. 115/1921.
12. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 263/1921
13. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 102/1921
14. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 1/1921
15. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 115/1921
16. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 144/1921
17. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 191/1921
18. बिहार विशेष शाखा 1921 भारत माता का संदेश पेफलेट अवैध घोषित किया, सीआईडी अभिलेख कक्ष पटना।
19. बिहार और उड़ीसा राजनीतिक फाइस सं. 44/1921
20. सिंह नेशनल मूवमेंट इन बिहार।